गुजरात उर्जा विकास निगम लिमिटेड

बनाम

ईएमसीओ लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 1220/2015)

02 फरवरी, 2016

[न्यायाधिपति चेलामेश्वर और अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधिपति]

बिजली- शुल्क निर्धारण- सौर ऊर्जा परियोजनाओं से गुजरात में वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली की खरीद के लिए- आयकर अधिनियम की धारा 32 और नियम के तहत त्वरित मूल्यह्रास के लाभ को ध्यान में रखते हुए दिनांक 29.1.2010 (पहला शुल्क आदेश) के आदेश द्वारा शुल्क निर्धारण- आदेश में उस परियोजना के लिए अलग शुल्क के निर्धारण का भी प्रावधान किया गया है, जिसे त्वरित मूल्यह्रास का लाभ नहीं मिला- अपीलकर्ता ने परियोजना के लिए प्रतिवादी-बिजली उत्पादक के साथ बिजली की बिक्री और खरीद के लिए बिजली खरीद समझौते (पीपीए) में प्रवेश किया। हालाँकि, पहले शुल्क आदेश के तहत निर्धारित नियंत्रण अवधि के भीतर बिजली का उत्पादन शुरू नहीं हो सका- एक अन्य आदेश दिनांक 27.1.2012 (दूसरा शुल्क आदेश) जो 29.1.2012 को या उसके बाद चालू होने वाली परियोजनाओं पर लागू शुल्क का निर्धारण करता है।

उत्पादक ने दूसरे शुल्क आदेश के बाद बिजली का उत्पादन शुरू किया- दूसरे शुल्क आदेश के अनुसार शुल्क का दावा करने की अनुमति के लिए राज्य आयोग को बिजली उत्पादक की याचिका की अनुमति दी गई- अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा राज्य आयोग के आदेश की पुष्टि की गई- अपील पर, ठहराया: कि शर्तें पीपीए बिजली उत्पादक को दूसरे शुल्क आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क का अधिकार नहीं देता है- 'त्वरित पदोन्नति का लाभ' आयकर अधिनियम से प्रवाहित होता है जो बिजली उत्पादक के विकल्प पर निर्भर था- पीपीए ऐसे लाभ का कोई संदर्भ नहीं देता है- विकल्प की उपलब्धता बिजली उत्पादक को पीपीए के तहत किए गए संविदात्मक दायित्वों से राहत नहीं देती है- इसलिए, बिजली उत्पादक दूसरे शुल्क आदेश के अनुसार शुल्क का हकदार नहीं है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. बिजली उत्पादन में लगे उपक्रम के पास आयकर अधिनियम की धारा 32(1)(i) के तहत योजना के अनुसार अपनी संपत्ति पर मूल्यह्रास का दावा करने का विकल्प है।

इस तरह के विकल्प का प्रयोग प्रासंगिक समय पर किया जा सकता है जैसा कि आयकर नियम, 1962 के नियम 5(1) के दूसरे प्रावधान में दर्शाया गया है। [अनुच्छेद 15][869-सी-डी]

2. दूसरे प्रतिवादी ने सभी वर्गों की परियोजनाओं के लिए शुल्क का प्रस्ताव रखा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वे सभी इसके हकदार होंगे आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत 'त्वरित मूल्यह्रास के लाभ' का दावा करने के लिए। दूसरे प्रतिवादी को माना जाना चाहिए कि प्रथम शुल्क आदेश को प्रतिपादित करते समय ज्ञात हुआ है कि आयकर अधिनियम और उसके तहत नियम निर्धारिती (बिजली के निर्माता) को 'त्वरित मूल्यह्रास के लाभ' का दावा करने या न करने का विकल्प प्रदान करते हैं। इसलिए, शर्त। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम शुल्क आदेश के तहत शुल्क उन बिजली उत्पादन परियोजनाओं पर लागू नहीं है जो कानून के अनुसार धारा 32(1)(i) के तहत योजना के लाभ का दावा करने के हकदार नहीं हैं। आयकर अधिनियम. [अनुच्छेद 18 और 16] [869-ई-एफ; 870-डी-ई]

3. पीपीए प्रतिवादी को पीपीए की शर्तों से बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं देता है। यह केवल इस संभावना की कल्पना करता है कि निर्माता प्रथम शुल्क आदेश के तहत निर्धारित "नियंत्रण अवधि" के भीतर अपनी परियोजना को चालू नहीं करेगा और यह प्रावधान करता है कि ऐसी स्थिति में प्रथम प्रतिवादी द्वारा बिजली की बिक्री पर लागू शुल्क क्या होना चाहिए। दूसरे, पीपीए प्रथम प्रतिवादी को दूसरे शुल्क आदेश द्वारा दूसरे प्रतिवादी द्वारा निर्धारित शुल्क का 'अधिकार' नहीं देता है। [अनुच्छेद 26] [875-ए-बी]

4. प्रथम प्रतिवादी का "त्वरित मूल्यह्रास का लाभ" न लेने का अधिकार आयकर अधिनियम से आता है। यह एफ केवल प्रथम शुल्क आदेश है जो प्रथम प्रतिवादी को एक विकल्प देता है (उस मामले के लिए सभी बिजली उत्पादक के लिए जो समान रूप से प्रथम प्रतिवादी के रूप में स्थित हैं) अपने द्वारा उत्पादित बिजली को प्रथम शुल्क आदेश में निर्दिष्ट मूल्य पर नहीं बेचेंगे बल्कि एक अलग शुल्क के निर्धारण की मांग करेंगे। ऐसा अधिकार और विकल्प बिजली के लिए उपलब्ध है। उत्पादक केवल एक आकस्मिकता में, यानी, कि वे 'त्वरित मूल्यह्रास का लाभ' लेने के इच्छुक नहीं हैं। [अनुच्छेद 26] [875-डी-ई]

5. आयकर अधिनियम उत्पादकों को एक विकल्प देता है या तो 'त्वरित मूल्यह्रास का लाभ' प्राप्त करने की शक्ति या नहीं। यह उस समय के बिंदु को भी निर्दिष्ट करता है जिस पर ऐसा विकल्प है उपयोग किया जा सकता है। नियम 5(1ए) के दूसरे प्रावधान में निर्दिष्ट समय पर ऐसे विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार केवल आयकर अधिनियम से मिलने वाले लाभों का लाभ उठाने के उद्देश्य तक सीमित है। पीपीए "त्वरित मूल्यह्रास के लाभों" का कोई संदर्भ नहीं देता है। इसने केवल अपीलकर्ता द्वारा प्रथम प्रतिवादी से खरीदी गई बिजली के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत निर्दिष्ट की। अपीलकर्ता ने विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद उक्त कीमत निर्धारित की। उनमें से एक यह हुआ कि बिजली उत्पादक आयकर अधिनियम के तहत कुछ 'लाभ' के हकदार हैं । ऐसे

'लाभ' की उपलब्धता बिजली उत्पादकों के विकल्प पर निर्भर है। हालांकि प्रथम शुल्क आदेश आईटी अधिनियम के अनुसार, धारा 32 के तहत एडी योजना के संदर्भ में 'लाभ' अभिव्यक्ति को नियोजित करता है, बिजली उत्पादक पर प्रावधान की प्रयोज्यता बिजली उत्पादक की पसंद पर निर्भर करती है। किसी मामले में एडी योजना की उपलब्धता बिजली उत्पादक के लिए फायदेमंद है या नहीं, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यह बिजली उत्पादक पर निर्भर करता है कि वह आंकलन करे कि एडी का लाभ लेना फायदेमंद है या नहीं और फिर यह निर्णय लेगा कि धारा 32 आईटी अधिनियम के तहत योजना का लाभ उठाया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन आईटी अधिनियम के तहत आय के आंकलन के उद्देश्य से बिजली उत्पादक को इस तरह के विकल्प की उपलब्धता बिजली उत्पादक को पीपीए के तहत किए गए संविदात्मक दायित्वों से राहत नहीं देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बिजली उत्पादक के रूप में प्रथम प्रतिवादी को पीपीए में प्रवेश करने से पहले या तो अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित कीमत को स्वीकार करने या नहीं करने के लिए अनुबंध की स्वतंत्रता है। लेकिन पीपीए में प्रवेश करने के बाद ऐसी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। [अनुच्छेद 28 और 29] [875-जी-एच; 876-ए-डी]

6. प्रथम प्रतिवादी ने पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हुए भी प्रश्नगत में पीपीए में प्रवेश किया, जिसमें स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 5.2 के तहत निर्धारित किया गया था कि "शुल्क सौर आधारित बिजली परियोजना

के लिए शुल्क आदेश दिनांक 29.1.2010 के तहत आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 2 और अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों ही देखने में विफल रहे और प्रथम प्रतिवादी ने पीपीए के अनुच्छेद 5.2 के अंतिम वाक्य में निहित पीपीए की एक महत्वपूर्ण शर्त को आसानी से नजरअंदाज कर दिया। उक्त शर्त में स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जहां पक्षों (पीपीए) के बीच अनुबंध के बावजूद, पहले प्रतिवादी के द्वारा प्रथम शुल्क आदेश में निर्धारित "नियंत्रण अवधि" के भीतर बिजली का उत्पादन शुरू करने में सक्षम नहीं होने की संभावना है। यह भी कल्पना की गई है कि बाद की नियंत्रण अवधि के लिए, परियोजनाओं/बिजली उत्पादकों (पहले प्रतिवादी के समान) को देय शुल्क भिन्न हो सकते हैं। उक्त दो कारकों की मान्यता में, पीपीए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया कि ऐसी स्थिति में, प्रथम प्रतिवादी दो शुल्कों में से केवल कम के लिए हकदार होगा। उक्त शर्त को दूसरे प्रतिवादी और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। [अनुच्छेद 30 और 31][876-ई-एच; 877-ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1220/2015

अपील संख्या 252/2013 में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 20.11.2014 से

अपीलार्थी के लिए सी. ए. सुंदरम, एम. जी. रामचंद्रन, हेमंतिका वाही, आनंद गणेशन, शुभम आर्य।

विकास सिंह, हेमंत सहाय, पूजा प्रियदर्शिनी, सावलोनी तंगरी, नर हरि सिंह, शाक्य सिंह चौधरी, शेखर प्रीत झा, डॉ. ऋचा दुबे उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

चेलमेश्वर, न्यायाधिपति।

1. यहां दूसरा प्रतिवादी, गुजरात विद्युत नियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 82 के तहत गठित एक निकाय है। अधिनियम की धारा 61(एच), 62(1)(ए) और 86(1)(ई) के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूसरे प्रतिवादी ने 2010 का आदेश संख्या 2 दिनांक 29.01.2010 ज़ारी किया (इसके बाद इसे कहा जाएगा) "प्रथम शुल्क आदेश") गुजरात में वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा सौर ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए शुल्क का निर्धारण करता है। उक्त आदेश गुजरात राज्य और भारत संघ के नीति दिशानिर्देशों सहित विभिन्न प्रासंगिक कारकों पर विस्तृत विचार के बाद ज़ारी किया गया था। उक्त आदेश के तहत, सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) प्रौद्योगिकी को नियोजित करने वाली परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न बिजली की खरीद के लिए शुल्क परियोजना के वाणिज्यिक

संचालन की तारीख से शुरू होने वाले शुरुआती 12 वर्षों के लिए 15 रुपये प्रति किलोवाट निर्धारित किया गया था और 13 वें वर्ष से 25 वें वर्ष तक रु.5 प्रति किलोवाट। उक्त आदेश 29.01.2010 से लागू हुआ घोषित किया गया। शुल्क निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखे गए विभिन्न वित्तीय और परिचालन मापदंडों का उल्लेख उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 में किया गया है ध्यान में रखे गए कारकों में से एक 'मूल्यह्रास की दर' है। आदेश के अनुच्छेद 5 में यह निर्दिष्ट है कि उक्त आदेश के तहत तय किए गए शुल्क में “आयकर अधिनियम और नियमों के तहत त्वरित मूल्यह्रास के लाभ को ध्यान में रखा गया है"। आगे यह घोषित किया गया है कि "ऐसी परियोजना के लिए जिसे ऐसा लाभ नहीं मिलता है, आयोग, उस संबंध में एक याचिका पर, सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक अलग शुल्क निर्धारित करेगा।"

2. प्रथम प्रतिवादी किसी एक परियोजना से विद्युत ऊर्जा (बिजली) का उत्पादन करता है। अपीलकर्ता और प्रथम प्रतिवादी ने गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में प्रतिवादी द्वारा स्थापित 5 मेगावाट परियोजना से बिजली की बिक्री और खरीद के लिए दिनांक 09.12.2010 को एक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) में प्रवेश किया। वर्तमान अपील में विवाद के लिए प्रासंगिक प्रावधान खंड 5.1 और 5.2 हैं।

"अनुच्छेद 5: दरें और शुल्क

5.1 मासिक ऊर्जा शुल्क: जीयूवीएनएल, एसएलडीसी द्वारा मासिक एसईए में प्रमाणित अनुसूचित ऊर्जा/ऊर्जा के लिए हर महीने बिजली उत्पादक को अनुच्छेद 5.2 में निर्धारित राशि ("शुल्क") का भुगतान करेगा।

5.2 जीयूवीएनएल सभी अनुसूचित ऊर्जा/ऊर्जा के लिए 25 वर्षों की अवधि के लिए यहां उल्लिखित निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा जैसा कि एसएलडीसी द्वारा मासिक एसईए में प्रमाणित है। शुल्क का निर्धारण माननीय आयोग द्वारा सौर ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजना के लिए शुल्क आदेश दिनांक 29.01.2010 के माध्यम से किया जाता है।

फोटोवोल्टिक परियोजना के लिए शुल्क:

पहले 12 वर्षों के लिए रु.15/किलोवाट इसके बाद, 13 वें वर्ष से 5 रुपये/किलोवाट 25 वें वर्ष तक ।

उपरोक्त शुल्क 31 दिसंबर 2011 को या उससे पहले शुरू की गई सौर परियोजनाओं के लिए लागू होगा। यदि सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने में 31 दिसंबर 2011 से अधिक की देरी होती है, तो जीयूवीएनएल उस तारीख से प्रभावी सौर परियोजनाओं के लिए माननीय जीईआरसी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा। सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने या उपर्युक्त शुल्क, जो भी कम हो।"

और उक्त पीपीए के खंड 12.8 और 12.10

3. हालाँकि, उपर्युक्त पीपीए में प्रवेश करने के बाद, प्रतिवादी सं. 1 ने परियोजना का स्थान बदलने का निर्णय लिया। इसलिए, उचित और आवश्यक संशोधन करते हुए दिनांक 07.05.2011 को अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच एक पूरक समझौता किया गया था। यद्यपि मूल पीपीए के अनुच्छेद 5.1 और 5.2 अपरिवर्तित रहे।

4. दूसरे प्रतिवादी ने 29.01.2012 को या उसके बाद चालू होने वाली परियोजनाओं पर लागू शुल्क का निर्धारण करते हुए दिनांक 27.01.2012 (इसके बाद "द्वितीय शुल्क आदेश" के रूप में संदर्भित) का एक और आदेश पारित किया। सौर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) प्रौद्योगिकी के माध्यम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के लिए उक्त आदेश के तहत निर्धारित शुल्क "आयकर अधिनियम के तहत त्वरित मूल्यह्रास का लाभ प्राप्त करना" बिजली उत्पादकों के लिए कम अनुकूल है और अपीलकर्ता द्वारा देय शुल्क बिजली उत्पादको जो आयकर अधिनियम के तहत "त्वरित मूल्यह्रास का लाभ" नहीं लेते हैं, ऐसे बिजली उत्पादकों के लिए यह अधिक अनुकूल है।

5. प्रथम प्रतिवादी ने अपनी परियोजना 2.3.2012 को शुरू की, यानी, प्रथम शुल्क आदेश के तहत निर्दिष्ट शुल्क की "नियंत्रण अवधि अनुच्छेद 7.2 नियंत्रण अवधि" से परे। उक्त "नियंत्रण अवधि" 28.01.2012 को समाप्त हुई। प्रथम प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि

आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत त्वरित मूल्यह्रास का लाभ नहीं उठाया।

6. इसलिए, प्रथम प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 86(1)(एफ) को लागू करते हुए राज्य आयोग के समक्ष एक याचिका संख्या 1270 /2012 दायर की और प्रार्थना की "(ए) यह माननीय आयोग इसे आयोजित करने और घोषित करने में प्रसन्न हो याचिकाकर्ता दिनांक 27.1.2012 के शुल्क आदेश के अनुसार त्वरित मूल्यह्रास का लाभ नहीं उठाने वाली मेगावाट पैमाने की सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं पर लागू शुल्क का दावा करने का हकदार है; और (बी) यह माननीय आयोग प्रतिवादी के दिनांक 20.4.2012, 22.6.2012 और 20.11.2012 के पत्रों में लिए गए मेगावाट पैमाने के सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं पर लागू शुल्क को अस्वीकार करने के निर्णय को दरकिनार करने और रद्द करने में प्रसन्न होगा। याचिकाकर्ता को शुल्क आदेश दिनांक 27.1.2012 के अनुसार त्वरित मूल्यह्रास और प्रतिवादी को तत्काल रुपये का भुगतान करने का निर्देश देना। याचिकाकर्ता को 59,50,260/- चालान की अंतर राशि दी गई है जिसका भुगतान प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है;"

7. द्वितीय प्रतिवादी ने अपने दिनांकित 08.08.2013 आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि प्रथम प्रतिवादी द्वितीय शुल्क आदेश दिनांकित 27.01.2012 में निर्दिष्ट शुल्क के लाभ का हकदार है। द्वितीय प्रतिवादी

ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि उसके न्यायिक आदेश का लाभ न केवल प्रथम प्रतिवादी को जाना चाहिए, बल्कि उन अन्य लोगों को भी जाना चाहिए जिन्होंने दूसरे प्रशुल्क आदेश के बाद में अपनी परियोजनाएं शुरू की हैं।

8. दिनांक 08.08.2013 के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 110 के तहत गठित विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद "अपीलीय न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित) के समक्ष अपील दायर की, जिसने धारा 111 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया।

9. विवादित आदेश दिनांक 20.11.2014 द्वारा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने दूसरे प्रतिवादी के आदेश की पुष्टि की।

अनुच्छेद 62. निष्कर्षों का सारांश:

(ए) दिनांक 30.1.2010 के आदेश के तहत राज्य आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क के लिए अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच पीपीए दिनांक 19.12.2010 को दर्ज किया गया। पहले 12 वर्षों के लिए 15 रुपये प्रति किलोवाट और उसके बाद 13 वें वर्ष से 25 वें वर्ष तक 5 रुपये प्रति किलोवाट, बशर्ते कि सौर परियोजना इस दिन या उससे पहले चालू की गई हो।

31 दिसंबर 2011 । हालाँकि, यदि परियोजना के चालू होने में 31 दिसंबर, 2011 से अधिक की देरी होती है, तो अपीलकर्ता को सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने की तारीख से प्रभावी राज्य आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रतिवादी संख्या 1 की सौर परियोजना 2.3.2012 को चालू की गई थी। इसलिए, 29.1.2012 से 31.3.2015 तक की अगली नियंत्रण अवधि के लिए राज्य आयोग के आदेश दिनांक 27.1.2012 द्वारा निर्धारित शुल्क प्रतिवादी संख्या 1 पर लागू होगा।

(बी) दिनांक 27.1.2012 के आदेश में, राज्य आयोग ने त्वरित मूल्यह्रास का लाभ उठाने वाले और त्वरित मूल्यह्रास का लाभ उठाए बिना सौर परियोजना के लिए शुल्क निर्धारित किया है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने त्वरित मूल्यह्रास का लाभ नहीं उठाया है, दिनांक 27.1.2012 के आदेश में त्वरित मूल्यह्रास के बिना निर्धारित शुल्क पीपीए और राज्य आयोग के शुल्क आदेश दिनांक 27.1.2012 के अनुसार लागू होगा।

(सी) दिनांक 27.1.2012 के शुल्क आदेश को पूरा पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राज्य आयोग ने त्वरित मूल्यह्रास का लाभ उठाने वाली परियोजनाओं और त्वरित मूल्यह्रास का लाभ नहीं उठाने वाली दोनों परियोजनाओं के लिए शुल्कनिर्धारित किया है। यह आदेश सोलर डेवलपर को त्वरित मूल्यह्रास का लाभ लेने या न लेने का विकल्प देता है।"

इसलिए, अधिनियम की धारा 125 के तहत तत्काल अपील।

10. दूसरे प्रतिवादी द्वारा जारी पहला शुल्क आदेश और दूसरा शुल्क आदेश दोनों बिजली उत्पादकों को देय शुल्क से संबंधित हैं। दोनों शुल्क आदेशों के बीच अंतर जहां तक यह वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, वह है:

प्रथम शुल्क आदेश ने उन परियोजनाओं के लिए शुल्क तय किया, जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत "त्वरित मूल्यह्रास का लाभ" मिलता है।

"जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, विभिन्न मापदंडों के आधार पर, सौर पीवी बिजली उत्पादन के आरओई सहित लेवलाइज्ड शुल्क, 10.19% की छूट दर का उपयोग करते हुए 12.54 रुपये प्रति किलोवाट तक काम करता है और सौर थर्मल पावर उत्पादन कार्यों के लिए समान डिस्काउंटिंग कारक का उपयोग करके लेवलाइज्ड शुल्क होता है 9.29 रुपये प्रति किलोवाट। हालांकि, आयोग का मानना है कि 25 वर्षों के लिए समान शुल्क के बजाय दो उप-अवधि: 12 वर्ष और 13 वर्ष के लिए शुल्क निर्धारित करना उचित होगा। इसलिए, आयोग शुल्क निर्धारित करता है सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन के लिए रु.15 परियोजना के

वाणिज्यिक संचालन की तारीख से शुरू होने वाले प्रारंभिक 12 (बारह) वर्षों के लिए 15 प्रति किलोवाट और रु13 (तेरहवें) वर्ष से 25 वें (पच्चीसवें) वर्ष तक 5 प्रति किलोवाट। आयोग सौर ताप विद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन के लिए रु.11 प्रति किलोवाट का शुल्क भी निर्धारित करता है परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से शुरू होने वाले प्रारंभिक 12 (बारह) वर्षों के लिए और रु4.00 प्रति किलोवाट 13 वें (तेरहवें) वर्ष से 25 वें (पच्चीसवें) वर्ष तक । उपरोक्त शुल्क आयकर अधिनियम और नियमों के तहत त्वरित मूल्यह्रास के लाभ को ध्यान में रखते हैं। ऐसी परियोजना के लिए जिसे ऐसा लाभ नहीं मिलता है, आयोग उस संबंध में एक याचिका पर सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक अलग शुल्क निर्धारित करेगा।"

(II) द्वितीय शुल्क आदेश ने, दूसरी ओर, परियोजनाओं की दोनों श्रेणियों के लिए शुल्क तय किया, अर्थात वे जो "त्वरित मूल्यह्रास का लाभ" उठाते हैं (आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत) और वे जो त्वरित मूल्यह्रास का लाभ" नहीं" लेते हैं ।

"इन तकनीकी और वित्तीय मापदंडों के आधार पर, त्वरित मूल्यह्रास का लाभ उठाने वाली मेगावाट-स्केल सौर

फोटोवोल्टिक बिजली परियोजनाओं के लिए इक्विटी पर रिटर्न सहित लेवलाइज्ड शुल्क की गणना 9.28 रुपये प्रति किलोवाट है, जबकि त्वरित मूल्यह्रास का लाभ नहीं उठाने वाली समान परियोजनाओं के लिए शुल्क की गणना की जाती है 10.37 रुपये प्रति किलोवाट होगा। आयोग दो उप-अवधि के लिए शुल्क निर्धारित करने का भी निर्णय लेता है। त्वरित मूल्यह्रास का लाभ उठाने वाले मेगावाट-स्केल फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के लिए, पहले 12 वर्षों के लिए शुल्क 9.98 रुपये प्रति किलोवाट होगा और बाद के 13 वर्षों के लिए वर्ष 7 रुपये प्रति किलोवाट होगा। इसी प्रकार, त्वरित मूल्यह्रास का लाभ नहीं उठाने वाली मेगावाट-स्केल फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के लिए, पहले 12 वर्षों के लिए शुल्क रु. 11.25 प्रतिकिलोवाट घंटा और अगले 13 वर्षों के लिए रु. 7.50 प्रति किलोवाट घंटा होगा।"

11. प्रथम प्रतिवादी का मामला यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि उसने प्रथम शुल्क आदेश में निर्दिष्ट "नियंत्रण अवधि" के दौरान पीपीए में प्रवेश किया है, वह अपीलकर्ता को अनुच्छेद 5.2 में निर्दिष्ट मूल्य पर बिजली बेचने के लिए बाध्य नहीं है। पीपीए का और कानूनी तौर पर (दूसरे प्रतिवादी से) एक अलग शुल्क के निर्धारण की मांग करने का हकदार है। यह पहले प्रतिवादी का मामला है कि पीपीए के तहत, अपीलकर्ता पहले

प्रतिवादी से बिजली खरीदने के लिए बाध्य है। 25 वर्ष की अवधि के लिए यदि प्रथम प्रतिवादी "नियंत्रण अवधि" के भीतर बिजली का उत्पादन शुरू करता है और पीपीए के अनुच्छेद 5.2 में निर्दिष्ट दरों पर इसके द्वारा खरीदी गई बिजली का भुगतान करने के लिए भी बाध्य है। लेकिन प्रथम प्रतिवादी की बाध्यता पीपीए के अनुच्छेद 5.2 में निर्दिष्ट दरों पर अपीलकर्ता को इसके द्वारा उत्पादित बिजली बेचने के लिए केवल दो आकस्मिकताओं के घटित होने पर ही अस्तित्व में आता है, अर्थात, प्रथम प्रतिवादी द्वारा (i) प्रथम शुल्क आदेश के तहत निर्धारित "नियंत्रण अवधि" के भीतर बिजली का उत्पादन शुरू करना ; और (ii) आयकर अधिनियम के तहत "त्वरित मूल्यह्रास का लाभ" का लाभ उठाना चुनना। प्रथम प्रतिवादी के अनुसार, प्रथम शुल्क आदेश के तहत यह शर्त कि उसके तहत निर्धारित शुल्क उन परियोजनाओं पर लागू नहीं है, जिन्हें "ऐसा लाभ नहीं मिलता है, आयोग उस संबंध में एक याचिका पर सभी को ध्यान में रखते हुए एक अलग शुल्क निर्धारित करेगा।" प्रासंगिक तथ्यों से केवल यह तात्पर्य नहीं होगा कि शुल्क आदेश के तहत निर्धारित शुल्क उन परियोजनाओं/बिजली उत्पादकों पर लागू नहीं है जो आयकर अधिनियम के तहत "त्वरित मूल्यह्रास का लाभ" नहीं लेते हैं।

12. दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं का मामला यह रहा है कि प्रथम प्रतिवादी को स्पष्ट रूप से पता था जब उसने पीपीए में प्रवेश किया था कि प्रथम शुल्क आदेश के तहत प्रस्तावित शुल्क केवल उन परियोजनाओं

के लिए लागू है जो "लाभ" का लाभ उठाते हैं त्वरित मूल्यह्रास" आयकर अधिनियम के तहत। यदि पहले प्रतिवादी का आयकर अधिनियम के तहत "त्वरित मूल्यह्रास का लाभ" प्राप्त करने का इरादा नहीं था, तो उसे दूसरे प्रतिवादी द्वारा शुल्क के निर्धारण की मांग किए बिना पीपीए में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। प्रथम प्रतिवादी को पीपीए में प्रवेश करने के लिए चुने जाने के बाद, प्रथम प्रतिवादी बाद के समय में यानी प्रथम शुल्क आदेश के तहत निर्धारित नियंत्रण अवधि से परे "त्वरित मूल्यह्रास का लाभ" नहीं लेने का निर्णय नहीं ले सकता है और अधिक लाभप्रद लाभ का दावा नहीं कर सकता है। दूसरे शुल्क आदेश में उन परियोजनाओं के पक्ष में शुल्क निर्धारित किया गया है जो "त्वरित मूल्यह्रास का लाभ" नहीं लेते हैं।

13. हमने पहले ही देखा है कि प्रथम प्रतिवादी ने प्रथम शुल्क आदेश के तहत निर्धारित "नियंत्रण अवधि" के भीतर बिजली का उत्पादन शुरू नहीं किया और आयकर अधिनियम के तहत "त्वरित मूल्यह्रास का लाभ" भी नहीं उठाया।

14. यह सर्वमान्य है कि प्रथम शुल्क आदेश और पीपीए में उल्लेखित "त्वरित मूल्यह्रास का लाभ" आयकर अधिनियम की धारा 32 (1)(i) के साथ आयकर नियमों के नियम 5(1ए) में निहित शर्त है। वे उस विधि और तरीके का प्रावधान करते हैं जिसमें एक निर्धारिती की संपत्ति

के मूल्यह्रास की गणना की जानी है। आयकर अधिनियम की धारा 32 (जहाँ तक प्रासंगिक हो) निम्नानुसार निर्धारित करता है: -

"32(1) के मूल्यह्रास के संबंध में -

(i) भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर, जो मूर्त संपत्ति हैं;

(ii) जानकारी, पेटेंट, कॉपीराइट, व्यापार चिह्न, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी या समान प्रकृति का कोई अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार, अप्रैल, 1998 के प्रथम दिन या उसके बाद अर्जित अमूर्त संपत्तियां।

स्वामित्व, पूर्णतः या आंशिक रूप से, निर्धारिती द्वारा और व्यवसाय या पेशे के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने पर, निम्नलिखित कटौतियों की अनुमति दी जाएगी -

(i) बिजली के उत्पादन या उत्पादन और वितरण में लगे किसी उपक्रम की संपत्ति के मामले में, निर्धारिती को उसकी वास्तविक लागत पर ऐसा प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है।"

विचारित नुस्खा आयकर नियम, 1962 के नियम 5(1ए) में पाया जाता है जो इस प्रकार है: -

"(1ए) 1 अप्रैल 1997 को या उसके बाद अर्जित संपत्ति के मूल्यह्रास के संबंध में अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत भत्ते की गणना इन नियमों के परिशिष्ट IA में तालिका के दूसरे कॉलम में निर्दिष्ट प्रतिशत पर की जाएगी पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्धारिती के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्धारिती के लिए वास्तविक लागत पर। उक्त नियम के दूसरे प्रावधान के तहत, यह आगे प्रदान किया गया है;

"बशर्ते कि अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा(1) उपक्रम खंड (i),में परिशिष्ट IA में निर्दिष्ट मूल्यह्रास के बजाय, इसके विकल्प पर, परिशिष्ट 1 के साथ पढ़े गए उप-नियम (1) के तहत मूल्यह्रास की अनुमति दी जा सकती है, यदि इस तरह के विकल्प का उपयोग नियत समय से पहले किया जाता है अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के तहत आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि,

(ए) आंकलन वर्ष 1998-99 के लिए, एक ऐसे उपक्रम के मामले में जिसने 1 अप्रैल, 1997 से पहले बिजली पैदा करना शुरू कर दिया था; और

(बी) किसी अन्य उपक्रम के मामले में, पिछले वर्ष से संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए जिसमें वह बिजली पैदा करना शुरू करता है:"

15. उपरोक्त निकाले गए परंतुक से देखा जा सकता है, बिजली उत्पादन में लगे एक उपक्रम के पास आयकर अधिनियम की धारा 32(1)(i) के तहत योजना के अनुसार अपनी संपत्ति पर मूल्यह्रास का दावा करने का विकल्प है। इस तरह के विकल्प का प्रयोग प्रासंगिक समय पर किया जा सकता है जैसा कि उक्त परंतुक में दर्शाया गया है।

16. पहले प्रतिवादी का तर्क यह रहा है कि प्रथम शुल्क आदेश में यह शर्त है कि "एक परियोजना जिसे ऐसा लाभ नहीं मिलता है..." का अर्थ केवल यह है कि उक्त आदेश के तहत प्रस्तावित शुल्क परियोजनाओं पर लागू नहीं होता है। जो आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत योजना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन नहीं करते हैं। दूसरी ओर, अपीलकर्ता का तर्क यह रहा है कि इस तरह के खंड का तात्पर्य केवल यह है कि प्रथम शुल्क आदेश के तहत शुल्क उन बिजली उत्पादन परियोजनाओं पर लागू नहीं है जो कानून के संचालन के कारण (लेकिन निर्धारितियों के उल्लंघन के कारण नहीं) आयकर अधिनियम की धारा 32(1)(i) के तहत योजना के लाभ का दावा करने के हकदार नहीं हैं।

17. हम इस प्रश्नगत की जांच नहीं करना चाहते हैं कि क्या आयकर अधिनियम के तहत बिजली उत्पादन में लगे किसी भी परियोजना/उपक्रम के लिए उन मामलों के अलावा धारा 32(1)(i) के संचालन के अंतर्गत आने की संभावना है। जहां "उपक्रम" ऐसे शासन द्वारा शासित नहीं होने का विकल्प चुनता है। किसी भी पक्ष ने निवेदन नहीं किया कि कानून में एक बिजली परियोजना को त्वरित मूल्यह्रास का लाभ नहीं मिलने की संभावना है।

18. तर्क के लिए यह मानते हुए कि कानून में ऐसी संभावना मौजूद है, अपीलकर्ता द्वारा प्रथम शुल्क आदेश के अनुच्छेद 5 के प्रासंगिक हिस्से पर जो निर्माण की मांग की गई है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से अतार्किक होगा। पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम प्रथम शुल्क आदेश के अनुच्छेद 5 के उस हिस्से को पुन: प्रस्तुत करते हैं:

उपरोक्त शुल्क आयकर अधिनियम और नियमों के तहत त्वरित मूल्यह्रास के लाभ को ध्यान में रखते हैं। ऐसी परियोजना के लिए जिसे ऐसा लाभ नहीं मिलता है, आयोग उस संबंध में एक याचिका पर सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक अलग शुल्क निर्धारित करेगा।"

यह अपीलकर्ता या दूसरे प्रतिवादी का मामला नहीं है कि आयकर अधिनियम की धारा 32(1)(i) कुछ परियोजनाओं पर लागू नहीं होती है।

बयान का आशय स्पष्ट है । दूसरे प्रतिवादी ने सभी वर्गों की परियोजनाओं के लिए शुल्क का प्रस्ताव इस बात को ध्यान में रखते हुए किया कि वे सभी आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत 'त्वरित मूल्यह्रास के लाभ' का दावा करने के हकदार होंगे। यह माना जाना चाहिए कि दूसरे प्रतिवादी को प्रथम शुल्क आदेश प्रस्तुत करते समय पता था कि आयकर अधिनियम और उसके तहत नियम निर्धारिती (बिजली के निर्माता) को त्वरित मूल्यह्रास के लाभ का दावा करने या न करने का विकल्प प्रदान करते हैं। इसलिए, शर्त । प्रथम शुल्क आदेश के उपरोक्त निकाले गए खंड के निर्माण के संबंध में अपीलकर्ता का प्रस्तुतीकरण अस्वीकार कर दिया गया है।

19. हालाँकि, इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। दो प्रश्नों की अभी भी जांच की जानी बाकी है, (i) भले ही प्रथम शुल्क आदेश के अनुच्छेद 5 के उपरोक्त निकाले गए हिस्से पर प्रथम प्रतिवादी द्वारा दी गई व्याख्या सही हो (वास्तव में यह अस्वीकृति का तार्किक परिणाम होगा) अपीलकर्ता की दलील), क्या प्रथम प्रतिवादी को पीपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद 'त्वरित मूल्यह्रास का लाभ' न लेने का विकल्प चुनने का अधिकार होगा? (ii) क्या आयकर अधिनियम के तहत प्रथम प्रतिवादी का अधिकार है, ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति होगी जिससे अपीलकर्ता पीपीए के तहत प्रथम प्रतिवादी द्वारा उत्पन्न बिजली खरीदने के लिए बाध्य होगा। 25 वर्षों की अवधि के लिए

बिना यह जाने कि प्रथम प्रतिवादी किस कीमत पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा?

20. ये प्रश्नगत द्वितीय प्रतिवादी के समक्ष उठाए गए और बहस की गई लेकिन दुर्भाग्यवश वचनबंधन पर आधारित तर्कों से मामला अनावश्यक रूप से जटिल हो गया था। मुद्दे पर ध्यान देने के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण ने दूसरे प्रतिवादी के दिनांक 8.8.2013 के आदेश को विस्तार से निकाला। जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "6.16 हालाँकि, यह भी एक तथ्य है कि उपरोक्त पीपीए के पक्षकार पीपीए के अनुच्छेद 5.2 के दूसरे अनुच्छेद में सहमत हुए हैं कि यदि याचिकाकर्ता की परियोजना आदेश संख्या 2 /2010 दिनांक 29.1.2010, की नियंत्रण अवधि के दौरान चालू नहीं होती है या तो पीपीए के अनुच्छेद 5.2 में सहमत शुल्क या परियोजना के चालू होने की तारीख पर आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क, जो भी कम हो, लागू होगा। इस प्रकार, उपरोक्त पीपीए मान्यता देता है याचिकाकर्ता के मामले में दो शुल्क लागू हैं। चूंकि याचिकाकर्ता की परियोजना 2.3.2012 को चालू की गई थी, यह शुल्क उद्देश्यों के लिए 27.01.2012 के आदेश संख्या 1/2012 की

नियंत्रण अवधि के अंतर्गत आती है, जिसका प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

XXX XXX XXX XXX

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि दोनों शुल्क यानी एक त्वरित मूल्यह्रास का लाभ प्राप्त करने वाली परियोजना के लिए और दूसरा त्वरित मूल्यह्रास का लाभ नहीं लेने वाली परियोजना के लिए आयोग द्वारा 29.01.2012 से 31.03.2015 की नियंत्रण अवधि के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं के लिए अनुमति दी गई है। ऐसा मामला होने पर, पीपीए के अनुच्छेद 5.2 और शुल्क आदेश संख्या 1/2012 दिनांक 27.01.2012 को पढ़ने पर, हमारा विचार है कि प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं है।"

[विवादित आदेश में दूसरे प्रतिवादी के आदेश का अंश निकाला गया]

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि दूसरे प्रतिवादी ने पीपीए में इस शर्त पर ध्यान दिया कि यदि प्रथम प्रतिवादी प्रथम शुल्क आदेश के तहत निर्दिष्ट नियंत्रण अवधि के दौरान परियोजना को चालू नहीं करता है

"..... या तो वह शुल्क जिस पर सहमति हुई थी या आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क जो भी कम हो, लागू होगा, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे

कि अनुच्छेद 5.2 और शुल्क आदेश संख्या 1/2012 दिनांक 27.01.2012 के ठोस अध्ययन पर, हमारा विचार है कि वर्तमान मामले में प्रोमिसरी एस्टोपल का सिद्धांत लागू नहीं है। दूसरे प्रतिवादी ने देखा कि प्रथम "प्रतिवादी द्वारा परियोजना को चालू नहीं करने की स्थिति में लागू शुल्क के संबंध में पी.पी.ए. की शर्त दो शुल्कों में से कम होगी। इस तरह की शर्त के कानूनी प्रभाव की जांच किए बिना, दूसरे प्रतिवादी ने द्वितीय शुल्क आदेश का विश्लेषण जो पी.पी.ए. की शर्त के कानूनी प्रभाव को निर्धारित करने के लिए न तो आवश्यक है (और न ही मांग की गई)।

दूसरे प्रतिवादी के उपरोक्त निकाले गए निष्कर्ष की शुद्धता के बारे में अपने विचार का आदेश दिया। हम केवल यह मान सकते हैं कि अपील न्यायाधिकरण ने दूसरे प्रतिवादी के तर्क और निष्कर्ष को मंजूरी दी क्योंकि इसने दूसरे प्रतिवादी के आदेश को उलट नहीं दिया।

22. प्रथम प्रतिवादी की प्रस्तुतियों में से एक जो थी कि न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया है कि यह मुद्दा 30 अप्रैल, 2013 को अपील संख्या 111 /2012 में न्यायाधिकरण के एक पूर्व रसना विपणन सेवा एलएलपी बनाम गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और अन्य (इसके बाद "आर.ए.एस.एन.ए. मामला" के रूप में संदर्भित) से सम्बंधित निर्णय द्वारा कवर किया गया है।

23. आरएएसएनए मामले के तथ्य इस प्रकार हैंः कि रसना एक बिजली उत्पादक, अपीलार्थी (जी.यू.वी.एन.एल.) के साथ 8.12.2010 पर बिजली खरीद समझौता किया। उक्त पी.पी.ए. के तहत, रसना ने प्रथम एस.टी.ए. शुल्क आदेश द्वारा निर्धारित दर पर बिजली बेचने पर सहमति व्यक्त की। आखिरकार, रसना ने प्रथम शुल्क आदेश में निर्धारित नियंत्रण अवधि के भीतर 31.12.2011 को अपना बिजली संयंत्र चालू किया। हालाँकि, रसना ने दूसरे प्रतिवादी के समक्ष एक याचिका दायर की जिसमें इस आधार पर बिजली की बिक्री के लिए विशिष्ट शुल्क के निर्धारण की प्रार्थना की गई कि रसना को त्वरित मूल्यह्रास लाभ नहीं मिलेगा। रसना के उक्त आवेदन का जीयूवीएनएल ने विरोध किया था। एक प्रारंभिक आपत्ति कि ऐसा आवेदन विचारणीय नहीं है, जीयूवीएनएल द्वारा इस आधार पर उठाया गया था कि रसना को पीपीए का लाभ प्राप्त हुआ है और उसके अनुसार भुगतान भी उसके द्वारा मांगी गई राहत की मांग करने से रोका गया है। दूसरे प्रतिवादी ने प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया। इसलिए, GUVNL अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष गया। उक्त अपील से निपटते हुए, न्यायाधिकरण ने जीयूवीएनएल द्वारा उठाई गई स्पष्ट आपत्ति पर ध्यान दिया कि रसना द्वारा पीपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद रसना द्वारा एक अलग शुल्क के निर्धारण के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

24. न्यायाधिकरण ने जीयूवीएनएल की उक्त आपत्ति को खारिज कर दिया। संक्षेप में, रसना मामले में न्यायाधिकरण का निष्कर्ष यह था कि पीपीए का निष्पादन किसी विशिष्ट शुल्क के निर्धारण की मांग करने के रसना के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। इस तरह के निष्कर्ष के लिए न्यायाधिकरण के कारण ये हैं कि (i) प्रथम शुल्क आदेश रसना जैसे बिजली उत्पादक के अधिकार को मान्यता देता है त्वरित मूल्यह्रास के लाभ का विकल्प चुनते हैं या नहीं चुनते हैं; (ii) शुल्क आदेश में कोई विशिष्ट शर्त नहीं है कि रसना जैसे बिजली उत्पादक जो त्वरित मूल्यह्रास का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें पीपीए में प्रवेश करने से पहले अपीलकर्ता को सूचित करना चाहिए; (iii) न ही किसी कानून के तहत कोई बाध्यता है जिसके द्वारा रसना पीपीए पर हस्ताक्षर करने से पहले इस तथ्य का खुलासा करने के लिए बाध्य है कि वह त्वरित मूल्यह्रास का लाभ नहीं उठाएगी।

25. रसना मामले के फैसले पर भरोसा करते हुए, ट्रिब्यूनल ने विवादित आदेश में एक निष्कर्ष दर्ज किया:

> "32. वर्तमान मामले में, राज्य आयोग के आदेश दिनांक 29.1.2010 में निर्दिष्ट नियंत्रण अवधि के दौरान सौर परियोजना चालू नहीं की जा सकी। इसलिए, पीपीए के संदर्भ में, प्रतिवादी संख्या 1 निर्धारित शुल्क का हकदार है।

राज्य आयोग ने आगामी आदेश दिनांक 27.1.2012 में कहा।

हम रसना मामले में न्यायाधीकरण के आदेश की सत्यता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम आश्वस्त नहीं है कि आदेश अंतिम हो गया है या नहीं । लेकिन हमारी राय है कि मौजूदा मामले में न्यायाधीकरण द्वारा रसना मामले के आदेश पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से गलत है। रसना मामले में, प्रार्थना इस पर लागू एक अलग शुल्क के निर्धारण के लिए थी। मौजूदा मामले में, प्रथम प्रतिवादी की प्रार्थना अलग शुल्क के निर्धारण के लिए नहीं है, बल्कि एक घोषणा के लिए है कि प्रथम प्रतिवादी दूसरे शुल्क आदेश के तहत निर्धारित शुल्क के लाभों का दावा करने का हकदार है।"

26. इसके अलावा, न्यायाधीकरण का निष्कर्ष वर्तमान मामले में गलत है । सबसे पहले पीपीए प्रतिवादी को पीपीए की शर्तों से बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं देता है। यह केवल इस संभावना की कल्पना करता है कि निर्माता प्रथम शुल्क आदेश के तहत निर्धारित "नियंत्रण अवधि" के भीतर अपनी परियोजना को चालू नहीं करेगा और यह प्रावधान करता है कि ऐसी स्थिति में प्रथम प्रतिवादी द्वारा बिजली की

बिक्री पर कितना शुल्क लागू होना चाहिए। दूसरे, पीपीए प्रथम प्रतिवादी को दूसरे शुल्क आदेश द्वारा दूसरे प्रतिवादी द्वारा निर्धारित "शुल्क" का 'अधिकार' नहीं देता है। दूसरी ओर, पीपीए स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि ऐसी स्थिति में;

> "31 दिसंबर 2011 को या उससे पहले शुरू की गई सौर परियोजनाओं के लिए उपरोक्त शुल्क लागू होगा। यदि सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने में 31 दिसंबर 2011 से अधिक की देरी होती है, तो जीयूवीएनएल उस तारीख से प्रभावी सौर परियोजनाओं के लिए माननीय जीईआरसी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने या उपर्युक्त शुल्क, जो भी कम हो।"

प्रथम प्रतिवादी को "त्वरित मूल्यह्रास का लाभ" न लेने का अधिकार आयकर अधिनियम से मिलता है। यह केवल प्रथम आदेश है जो प्रथम प्रतिवादी को एक विकल्प देता है (उस मामले के लिए सभी बिजली उत्पादकों को जो प्रथम प्रतिवादी के समान रूप में स्थित हैं) अपने द्वारा उत्पादित बिजली को प्रथम शुल्क आदेश में निर्दिष्ट मूल्य पर बेचने के लिए नहीं बल्कि एक अलग शुल्क के निर्धारण की मांग करते हैं। ऐसा अधिकार और विकल्प बिजली उत्पादकों के लिए केवल एक आकस्मिक

स्थिति में उपलब्ध है यानी, वे 'त्वरित मूल्यह्रास का लाभ' लेने के इच्छुक नहीं हैं।

27. वास्तविक प्रश्नगत यह है: वह कौन सा समय है जब बिजली उत्पादक एक अलग शुल्क के निर्धारण की मांग करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

28. आयकर अधिनियम बिजली उत्पादकों को 'त्वरित मूल्यह्रास का लाभ' लेने या न लेने का विकल्प देता है। यह उस समय के बिंदु को भी निर्दिष्ट करता है जिस पर इस तरह के विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। नियम 5(1ए) के दूसरे प्रावधान में निर्दिष्ट समय पर ऐसे विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार केवल आयकर अधिनियम से मिलने वाले लाभों का लाभ उठाने के उद्देश्य तक सीमित है। पीपीए "त्वरित मूल्यह्रास के लाभों" का कोई संदर्भ नहीं देता है। इसने केवल अपीलकर्ता द्वारा प्रथम प्रतिवादी से खरीदी गई बिजली के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत निर्दिष्ट की। अपीलकर्ता ने उक्त कीमत निर्धारित की विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद उनमें से एक हुआ कि आयकर अधिनियम के तहत बिजली उत्पादक कुछ निश्चित 'लाभों' के हकदार हैं। ऐसे 'लाभ' की उपलब्धता बिजली उत्पादकों के विकल्प पर निर्भर है । यद्यपि प्रथम शुल्क आदेश आयकर अधिनियम की धारा 32 के तहत एडी योजना के संदर्भ में 'लाभ' अभिव्यक्ति को नियोजित करता है, बिजली उत्पादक के

लिए प्रावधान की प्रयोज्यता बिजली उत्पादक की पसंद पर निर्भर करती है। किसी दिए गए मामले में एडी योजना की उपलब्धता बिजली उत्पादक के लिए फायदेमंद है या नहीं, यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिनके विवरण की हम जांच करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। यह बिजली उत्पादक को यह आंकलन करना है कि एडी का लाभ उठाना फायदेमंद है या नहीं, यह निर्णय लिया जाएगा कि आयकर अधिनियम धारा 32 के तहत योजना का लाभ उठाया जाना चाहिए या नहीं।

29. लेकिन आयकर अधिनियम के तहत आय के अंकलन के प्रयोजन के लिए बिजली उत्पादक को इस तरह के विकल्प की उपलब्धता पीपीए के तहत किए गए संविदात्मक दायित्वों से बिजली उत्पादक को राहत नहीं देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बिजली उत्पादक के रूप में प्रतिवादी को पीपीए में प्रवेश करने से पहले या तो अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित कीमत को स्वीकार करने या नहीं करने के लिए अनुबंध की स्वतंत्रता है। लेकिन पीपीए में प्रवेश करने के बाद ऐसी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है।

30. प्रथम प्रतिवादी ने पूरी तरह से जानते हुए भी प्रश्नगत में पीपीए में प्रवेश किया, जिसमें स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 5.2 के तहत निर्धारित किया गया था कि "शुल्क का निर्धारण माननीय आयोग द्वारा

सौर आधारित बिजली परियोजना के लिए शुल्क आदेश दिनांक 29.1.2010 के तहत किया जाता है"

31. इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 2 और अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों नोटिस करने में विफल रहे और प्रथम प्रतिवादी ने पीपीए के अनुच्छेद 5.2 के अंतिम वाक्य में निहित पीपीए की एक महत्वपूर्ण शर्त को आसानी से नजरअंदाज कर दिया: -

> "यदि सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने में 31 दिसंबर 2011 से अधिक की देरी होती है, तो जीयूवीएनएल सौर ऊर्जा परियोजना के लिए माननीय जीईआरसी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा, जो सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने की तारीख से प्रभावी होगा या उपरोक्त शुल्क जो भी कम हो।"

उक्त शर्त में स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जहां पक्षों (पीपीए) के बीच अनुबंध के बावजूद, पहले प्रतिवादी द्वारा प्रथम शुल्क एडेस्क में निर्धारित "नियंत्रण अवधि" के भीतर बिजली का उत्पादन शुरू करने में सक्षम नहीं होने की संभावना है। यह भी कल्पना की गई कि बाद की नियंत्रण अवधि के लिए, परियोजनाओं/बिजली उत्पादकों (पहले प्रतिवादी के समान) को देय शुल्क भिन्न हो सकते हैं। उक्त दो कारकों की मान्यता में, पीपीए ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि ऐसी स्थिति में,

प्रथम प्रतिवादी दोनों शुल्क में से कम के लिए हकदार होगा। दुर्भाग्य से, उक्त शर्त को दूसरे प्रतिवादी और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। किसी भी आदेश में उक्त शर्त के बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं है।

32. प्रथम प्रतिवादी ने पर्याप्त भ्रम पैदा किया। जहां एक ओर प्रथम प्रतिवादी ने प्रथम शुल्क में निहित शर्त के मद्देनजर प्रथम शुल्क आदेश के तहत निर्धारित शुल्क से स्वतंत्र एक अलग शुल्क के निर्धारण की मांग करने का अधिकार जताया। आदेश दिया गया कि "ऐसी परियोजना के लिए जिसे ऐसा लाभ नहीं मिलता है, आयोग उस संबंध में एक याचिका पर, सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक अलग शुल्क निर्धारित करेगा" एक अलग शुल्क निर्धारित करने के लिए दूसरे प्रतिवादी से पहले राहत नहीं मांगी। लेकिन दूसरे शुल्क आदेश के लाभ का दावा किया। तर्क के लिए यह मानते हुए कि प्रथम प्रतिवादी (1270/2012) द्वारा दायर याचिका को अलग शुल्क के निर्धारण के लिए एक आवेदन के रूप में माना जाना चाहिए जो दूसरे शुल्क आदेश के तहत निर्धारित शुल्क के समान होगा, चाहे प्रथम प्रतिवादी इस तरह की राहत के लिए हकदार होगा, यह निर्भर करता है, यदि वह "सभी प्रासंगिक तथ्यों" पर विचार करने पर ऐसा निर्धारण करने का हकदार है, लेकिन दूसरे शुल्क आदेश के संचालन के आधार पर नहीं।

33. उपर्युक्त सभी कारणों से, हमारी राय है कि विवादित आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसलिए इसे रद्द किया जाता है। परिणामस्वरूप, दूसरे प्रतिवादी का दिनांक 8.8.2013 का आदेश, जो कि विवादित आदेश में अपील का विषय था, को भी रद्द कर दिया गया है।

34. इस समय, हमें यह उल्लेख करने की आवश्यकता है कि उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने बहुत दृढ़ता से तर्क दिया कि तत्काल अपील सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि विद्युत अधिनियम की धारा 125 में कहा गया है कि उक्त प्रावधान के तहत इस न्यायालय में अपील केवल वहीं सुनवाई योग्य है जहां कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्नगत है और इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग करने की मांग करने वाले पक्षों को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि इस न्यायालय के विचार के लिए कानून का महत्वपूर्ण प्रश्नगत क्या है। उत्तरदाताओं के अनुसार, अपील का ज्ञापन कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्नगत का खुलासा नहीं करता है जो इस न्यायालय के विचार के लिए उठता है।

35. हमें निवेदन में कोई तथ्य नहीं मिला। हमारा मानना है कि इस निर्णय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में बहस इस न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग को उचित ठहराने वाले कानून के एक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के इर्द-गिर्द घूमती रही। रुपये की निर्धारित लागत के साथ अपील स्वीकार की जाती है यहां प्रथम प्रतिवादी द्वारा 2 लाख का भुगतान

किया जाएगा। पहले दिए गए अंतरिम आदेश समाप्त हो गए हैं। इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, को भविष्य के लिए प्रथम प्रतिवादी को देय भुगतान में समायोजित किया जाएगा। अपीलकर्ता द्वारा बिजली की खरीद उस तरीके से की जाएगी जो अपीलकर्ता उपयुक्त और उचित समझे।

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।